materials, etc. for AIR Stations and the Industry;

10. Preparation of standard tapes for AIR stations.

(c) Based on the study projects and Research and development work a number of papers were presented at the Asian Broadcasting Union Conference, the Commonwealth Broadcasting Conference etc.

2. Following are some of the important items of equipment developed indigenously during the three years under review:

12" transistorised TV receivers

2Watt TV Translator

FM transmitter and receivers

Low cost mediumwave receiver

Transistorised distortion and noise level metre etc.

बिहार के आदिवासियों द्वारा कथित प्रदर्शन

1482. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के आदिवासियों ने अपने हाथों में धनुषबाण लेकर अपनी इस मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया है कि 'संथाल परगना अखण्ड रहेगा'; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी मांग पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले में कुछ स्थानों पर संथाल परगना को दो जिलों में विभाजित करने के विरुद्ध बैठकें और प्रदर्शन हुए थे। किन्तु यह सूचना नहीं है कि ये प्रदर्शनकारी धनुषबाण से लैस थे।

राज्य सरकार ने संथाल परगना को दो जिलों में विभाजित करने के लिये कोई निर्णय नहीं किया है।

विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों को उचित स्थान

1483. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों को उचित स्थान दिलाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विदेशी फर्मों में भारतीय कर्मचारियों को उचित स्थान दिलाने के बारे में समय-समय पर सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन फर्मों की तकनीकी और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विदेशी नागरिकों के उच्च प्रशासकीय और तकनीकी पदों का भारतीयकरण करना सरकार की नीति है।

विगत कुछ वर्षों से 3,000 रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले भारतीय कर्मचारियों की प्रतिशत बढ़ रही है। इस समय 3,000 रुपये तक प्रतिमास वेतन वाले सभी पदों पर व्यावहारिक रूप से भारतीय नागरिक ही कार्य कर रहे हैं।

"गरीबी हटाओ" कार्यक्रम

1484. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "गरीबी हटाने" के लिये किसी विसूती कार्यक्रम की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप देश से गरीबी कब तक हटाई जा सकेगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए "पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक प्रलेख जिसे दिल्ली मे 30 तथा 31 मई, 1972 की बैठकों मे राष्ट्रीय विकास परिषद ने अनुमोदित किया और जिसे सभा पटल पर रख दिया गया है—मे विकास कार्यक्रम के प्रति पाचवी योजना की नीति की विस्तृत रूपरेखा दी गई है। इसका मुख्य विषय "गरीबी हटाओं" है । इस कार्यक्रम मे मुख्य रूप से बल बेरोजगारी, अर्ध-रोजगारी तथा अत्यधिक गरीबी की समस्याओं पर सीधा प्रहार करने पर दिया जायेगा । इस समय योजना की पूरी रूपरेखा तैयार करने का विस्तृत कार्य चल रहा है । गरीबी की समस्या की विशालता को देखते हुए देश मे गरीबी हटने की निश्चित अवधि बताना एक पूर्व कथन होगा ।

Setting up of Industries in Backward Areas

1485. SHRI Y. ESWARA REDDY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) the provision made in the Fourth Five Year Plan for setting up industries in the backward areas;

(b) the progress made in the setting up of industries in these areas;

(c) the number of units set up in backward areas in the first three years of the Fourth Plan with Statewise break up; and

(d) what progress is expected to be achieved in this field in the remaining period of the Plan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (d). A total provision of Rs. 5 crores has been made at the Centre under the Fourth Five Year Plan for the Central Schemes of 10% subsidy and transport subsidy for promotion of industries in selected industrially backward districts/areas. Against this provision, under the 10% Central subsidy scheme, 3 State Governments and a Union Territory have so far sanctioned (not yet disbursed) a total amount of Rs. 9,87,691/- to 62 industrial units located in backward areas, as detailed below:—

Tamilnadu .	Rs. 5,86,667	(12 units)
Goa, Daman and Diu .	Rs. 3,50,358	(31 units)
Mysore .	Rs 29,110	(7 units)
Gujarat .	Rs. 21,556	(12 units)

Independent of this, licences under the Industries Act have been granted for units in backward areas as under:—

	1969	1970	1971
Assam . . .	1	1	4
Andhra Pradesh .	2	1	5
Bihar . . .	1	6	4
Gujarat . . .	1	3	4
Haryana . .	..	2	1
Jammu & Kashmir	..		1
Madhya Pradesh .	..	.	9
Maharashtra .	3	15	6
Mysore . . .	1	4	6
Orissa . . .	1	1	1
Punjab . . .	..	2	..
Rajasthan . .	..	2	7
Tamilnadu . .	2	13	12
Uttar Pradesh .	..	1	4
West Bengal . .	5	8	12
	17	59	76

Government have recently decided to increase the number of districts eligible for the 10% Central subsidy scheme. It is hoped that with the various measures already initiated for promotion of industries in the backward areas by the Centre and the State Governments and with the initiative and enterprise of the entrepreneurs substantial progress will be achieved in this regard during the remaining period of the Fourth Plan.